"That a Joint Committee of the Houses to be called the Joint Committee on Offices of Profit be constituted consisting of fifteen members, ten from this House and five from the Rajya Sabha, who shall be elected from amongst the Members of each House in accordance with the system of proportional representation by means of single transferrable vote;

That the functions of the Joint Committee shall be-

(i) to examine the composition and character of all existing "committees" (other than those examined by the Joint Committee to which the Parliament (Prevention of Disqualification) Bill, 1957 was referred) and all "committees" that may hereafter be constituted, membership of which may disqualify a person for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament under article 102 of the Constitution;

(ii) to recommend in relation to the "committees" examined by it what offices should disqualify and what offices should not disqualify;

(iii) to scrutinise from time to time the Schedule to the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, and to recommend any amendments in the said Schedule, whether by way of addition, omission or otherwise;

That the Joint Committee shall, from time to time, report to both Houses of Parliament in respect of all or any of the aforesaid matters;

That the members of the Joint Committee shall hold office for the duration of the present Lok Sabha;

That in order to constitute a sitting of the Joint Committee, the quorum shall be one-third of the total number of members of the Committee:

That in other respects, the rules of procedure of this House relating to Parliamentary Committees will apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

That this House recommends to the Rajya Sabha that the Rajya Sabha do join in the said Joint Committee and to communicate to this House the names of members to be appointed by the Rajya Sabha to the Joint Committee."

GENERAL DISCUSSION

[#]The Union Budget, 2024-25 - *Contd.*

[#] Discussed together.

&

#The Budget of Union Territory of Jammu & Kashmir, 2024-25 - *Contd.*

श्री उपसभापतिः माननीय सदस्यगण, मैं पुनः नाम लेना चाहूंगा। माननीय श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चा - अनुपस्थित; माननीय श्री जी.सी. चन्द्रशेखर; अनुपस्थित। माननीय श्री रामजी लाल सुमन, आपके पास 5 मिनट हैं।

श्री रामजी लाल सुमन (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, 2024-25 का जो बजट है, इसमें कृषि के लिए 1 लाख, 52 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। देश की आधी से ज्यादा आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है और यह सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। कुछ भी कहा जाता रहा हो, लेकिन मेरा आरोप है कि कृषि की उपेक्षा हुई है। महोदय, 2019-2020 के कुल बजट का 5.44 प्रतिशत कृषि के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन इस बजट में यह आवंटन 3.15 प्रतिशत है। उपसभापति महोदय, आप जानते हैं कि लंबे समय तक किसानों ने आंदोलन किया और किसान फिर से सिंघू बॉर्डर पर इकट्ठे हो रहे हैं। अगर सरकार गंभीरता से किसानों की समस्या पर गौर नहीं करेगी, तो इस देश में तनाव बढ़ेगा और मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि अगर तनाव बढ़ेगा, तो इसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ दल की होगी।

उपसभापति महोदय, बजट में यह कहा गया है कि हम प्राकृतिक खेती का प्रयोग करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि प्राकृतिक खेती नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। जहाँ तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल है, किसानों के आंदोलन के बाद 22 जुलाई, 2022 में एक कमेटी बनी थी, लेकिन अभी तक उसकी सिर्फ 6 मीटिंग्स हुई हैं। सरकार के पास किसानों की समस्या को हल करने का कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं है।

उपसभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि पिछले 7 वर्षों में जीएसटी का जो कर संग्रह है, वह 170 फीसदी बढ़ गया है। जीएसटी का 66 फीसदी हिस्सा 50 फीसदी गरीब लोगों से मिलता है। जीएसटी का कर संग्रह बढ़ गया है, लेकिन महंगाई ज्यादा बढ़ी है। छोटे व्यापारियों को जीएसटी से नुकसान हुआ है और इतने कर संग्रह के बावजूद भी राजस्व घाटा क्यों है? दिसंबर, 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, 20 से 24 वर्ष तक के युवा 44 प्रतिशत बेरोजगार थे। 25 से 29 वर्ष तक के 14 फीसदी युवा हमारे देश में बेरोजगार हैं। उपसभापति महोदय, शांता कुमार कमेटी सरकार ने बनाई थी और शांता कुमार कमेटी की यह सिफारिश है, शांता कुमार कमेटी का यह निष्कर्ष है कि हमारे देश में सिर्फ छः फीसदी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलता है। 94 फीसदी किसान को खुले बाजार में अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। उपसभापति महोदय, जो सार्थक प्रयास किसी को समृद्ध करने के लिए हमारे देश में होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। हमारे देश में 7,000 मंडियाँ हैं, जबकि 42,000 मंडियों की आवश्यकता है। उपसभापति महोदय, आज स्थिति क्या है? जिन किसानों की बात हम करते हैं,

तो खेत की दवाइयों पर 18 परसेंट जीएसटी है, ट्रेक्टर पर 28 परसेंट जीएसटी है, बीजों पर 12 फीसदी जीएसटी है, कृषि यंत्रों पर 28 फीसदी जीएसटी है। अगर सरकार सही मायनों में किसानों के साथ इंसाफ करना चाहती है, तो इन लोगों को जीएसटी को जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान करना चाहिए। उपसभापति महोदय, सरकार कहती है कि किसान अपनी फसल जहाँ चाहे बेच सकता है। भारत में 86 फीसदी किसान ऐसे हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है। क्या वे अपने उत्पाद को कहीं भी बेच सकते हैं। उपसभापति महोदय, यह संभव ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि... अभी कृषि मंत्री जी ने और हमारे लायक दोस्तों ने खेती के सवाल पर बड़ा हल्ला किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाली जो कमेटी है, वह कृषि मंत्रालय के अधीन है, एक संयुक्त सचिव उसका अध्यक्ष होता है। उसमें कृषि वैज्ञानिक नहीं हैं, किसानों के नुमाइंदे नहीं हैं। उपसभापति महोदय, जिन लोगों को यह जानकारी नहीं है कि चने का पेड़ बड़ा होता है या गेहूँ का पेड़ बड़ा होता है, वे किसान के भविष्य को तय करेंगे। ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापतिः माननीय सदस्य, आपका समय खत्म हुआ।

श्री रामजी लाल सुमनः उपसभापति जी, प्लीज़ दो मिनट लूँगा।

उपसभापति महोदय, किसान को अधिक उत्पादन का लाभ मिलेगा, यह संभव नहीं है। हमारे देश में खाद्य के भंडारण की व्यवस्था नहीं है। अभी कहा गया कि किसान बहुत खुशहाल है। महाराष्ट्र में जनवरी से जून तक 1,267 किसानों ने आत्महत्या की है। उपसभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इस देश में जो विकास का मॉडल अख्तियार किया गया, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जब तक कृषि पर आधारित बजट और श्रम पर आधारित उद्योग हमारे देश में नहीं लगेंगे, इस देश के हालातों को सुधारा नहीं जा सकता है। बजट से बहुत लोगों को अपेक्षाएं थीं, किसानो को, मजदूरों को, लेकिन बजट ने आम लोगों को निराश ही किया है और उसके संदर्भ में, मैं यह कहूँ तो बिल्कुल ठीक है –

'*मुंतजिर थे आमदे फसले बहार के*
ऐसी बहार आई कि गुलशन जला दिया।'

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश): सर, आज बजट की इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए मैं आपका, सभापति जी का, माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी का और हमारे सदन के नेता जे. पी. नड्डा जी का हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ।

मैं सबसे पहले इस देश की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्रधान मंत्री, मोदी जी के नेतृत्व में हमें इस देश की सेवा करने का तीसरी बार मौका दिया है। हम लोगों को 62 साल बाद ऐसा मौका मिल रहा है और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि इस मौके पर हम लोग इस देश की सेवा करेंगे, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। 2014 में जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने सरकार बनाई

थी, तब उन्होंने यह कहा था कि यह सरकार, पिछड़ों, किसानों और हर तबके के लोगों के जीवन में सुधार लाने का कार्य करेगी। साथ ही साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए विश्व पटल पर नई ऊंचाइयां छूने के लिए बिना किसी भेदभाव के कार्य करेगी। मैं यह कह सकता हूं कि इन 10 सालों में इन सभी बातों को ध्यान में रखकर कार्य किए गए हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में देश ने उन ऊंचाइयों को छुआ है, जो पिछले 60 सालों में नहीं हो पाया।

माननीय मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो पिछले 24 साल से संसदीय कार्यों में लगे हुए हैं और उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है और 24 घंटे देश की सेवा कर रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक बजट पेश किया है और उन्होंने सात बार इस बजट को पेश करने का एक रिकॉर्ड बनाया है। यह हमारे प्रधान मंत्री जी की जो वुमेन-लैड डेवलपमेंट की मिसाल है, वह इससे पूरी तरह से दिखती है। यह बजट 2047 के विकसित भारत के हमारे संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। यह हमारे देश के हर वर्ग गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, मजदूर, व्यापारी, उद्योगों की वृद्धि व सभी के हितों का ध्यान रखता है।

मैं उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता हूं। यहां हमारी डबल इंजन की सरकार है और वह विकास के नए मापदंड स्थापित कर रही है, चाहे वह औद्योगिक विकास हो, हाइवे हो, एक्सप्रैस वे हो, स्टार्ट-अप हो या बेहतर कानून व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आज अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज विश्व के प्रमुख देश, चाहे वह अमेरिका हो, रूस हो या यूरोपीय राष्ट्र हों, सभी भारत में हो रहे विकास की सराहना कर रहे हैं। भारत का डंका विश्व भर में गूंज रहा है और यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। परचेंजिंग पावर पैरिटी के संदर्भ में विश्व जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10 परसेंट है। आज भारत प्रथम तीन देशों में होगा। आज अगर हम विदेश जाते हैं, तो हमारे पासपोर्ट को बहुत इज्जत के साथ देखा जाता है। यही नहीं, हमारे पीपीपी के संदर्भ में जीडीपी के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2023 में 2.5 परसेंट से घटकर 2024 में 1.4 परसेंट रहने की उम्मीद है। दूसरी तरफ चीन में विकास दर 2024 में 4.7 रहने की उम्मीद है और एक तरफ भारत है जो 2024 में 6.2 परसेंट की दर से आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है। हमारी सरकार देश के हर कोने में विकास पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, चाहे वह इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र हो, रक्षा क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या शहरी विकास हो, हमारा संकल्प है कि हर क्षेत्र में सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक लाभ पहुंचाएंगी। 2004 से 2014 तक हुए विकासों की तुलना में हमारी सरकार ने 2014 से 2024 के दशक में कई गुणा अधिक प्रगति की है। हमारी सरकार अपने वादों को एक मिशन की तरह पूरा करने में दृढ़ विश्वास रखती है। यह बजट न केवल हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव को दर्शाता है, बल्कि भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है। सबसे पहले मैं आपका ध्यान अपनी अर्थव्यवस्था की अभूतपूर्व प्रगति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। 2014 में जब मोदी सरकार ने कार्यभार संभाला, तब हम विश्व की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। आज 2024 में हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। यह उपलब्धि कोरोना और जियो पॉलिटिकल चुनौतियों के बावजूद हासिल की गई है। यह गर्व की बात है कि भारत के कुल बजट के आकार में पिछले एक दशक में तीन गुना की वृद्धि हुई है।

2013-14 में हमारा कुल बजट आकार 16.65 लाख करोड़ था। 2024-25 में यह बढ़कर 48.21 लाख करोड़ हो गया है।

5.00 P.M.

यह वृद्धि न केवल हमारी अर्थव्यवस्था के आकार में विस्तार को दर्शाती है, बल्कि यह हमारी सरकार की दूरदर्शी नीतियों और सुधारों का भी परिणाम है। 2004 से 2014 तक कुल मिलाकर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सिर्फ 12.4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि पिछले 10 वर्षों में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 44 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार, दोनों बढ़ते हैं। इस साल बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 11.1 लाख करोड़ रुपए allot हुए हैं। जीडीपी का 3.4 परसेंट इंफ्रा पर खर्च किया जा रहा है।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी)** *पीठासीन हुए*]

कोरोना महामारी के कारण हमारी सरकार को पूरे तरीके से सिर्फ 8 साल काम करने का मौका मिला है, लेकिन इस दौरान भी देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों तक ले जाने का काम किया गया है। महामारी के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था कई विकसित देशों से भी ज्यादा स्थिर थी। हमने 10 साल में 20 सालों का विकास किया। देखा जाए तो यह double growth का काम है। हमारी सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है - inclusive growth के साथ-साथ भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना। भारत की अर्थव्यवस्था अभी 3.1 ट्रिलियन डॉलर की है। आजादी के बाद से भारत को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में 60 साल लगे थे, जबकि 1 ट्रिलियन से 3.1 ट्रिलियन तक का सफर हमने सिर्फ 10 सालों में पूरा किया है, जिसमें से 2 वर्ष कोरोना की महामारी के लिए भी निकले हैं। बढ़ती हुई रफ्तार के कारण भारत अगले 14-15 सालों तक हर दो साल में अपनी अर्थव्यवस्था में औसतन 1 ट्रिलियन डॉलर जोड़ सकेगा। Centre for Economics and Business Research की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2035 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन कर आगे आएगा। वित्तीय स्थिरता हमारी प्राथमिकता रही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारा fiscal deficit, जो वित्त वर्ष 2021 में 9.2 परसेंट था, वित्त वर्ष 2024 में घट कर 5.6 परसेंट हो गया है। 2024-25 के बजट में हम इसे और कम करके 4.9 परसेंट तक लाने का लक्ष्य रखते हैं। हमारा पहले का जो रिकॉर्ड रहा है, उसके हिसाब से मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम इसे पूरा कर सकेंगे।

हमारे प्रधान मंत्री जी का यह सपना रहा है कि हर गरीब के पास अपना मकान हो। वह न केवल उनके अपने घर बनवा रहे हैं, बल्कि उनको एक सम्मानपूर्ण जीवन भी दे रहे हैं। देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 2024-25 के केंद्रीय बजट में 3 करोड़ अतिरिक्त घरों की घोषणा की गई है। अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता के साथ पीएम आवास योजना-2 के माध्यम से एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों

के आवास को पूरा किया जाएगा और इससे अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। इन मकानों के साथ-साथ राशन, जल, बिजली, स्वास्थ्य और सौर ऊर्जा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। 'प्रधान मंत्री सूर्य घर योजना' के तहत अब भारत सरकार एक करोड़ लोगों के घरों में रूफटॉप सोलर पैनल भी लगा रही है। यह हमारी ग्रीन एनर्जी और इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रति जो प्राथमिकता है, उसका प्रमाण है।

हाल के वर्षों में भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। विशेषकर रेरा कानून के लागू होने के बाद इस कानून ने घर खरीदारों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है, उनको एक भरोसा दिया है और रियल एस्टेट उद्योग में निवेश को बढ़ावा भी मिल रहा है। पहले की सरकारों की तुलना में अब परियोजनाएँ समय पर पूरी हो रही हैं, जिससे नागरिकों को बेहतर सेवा मिल रही है, जिसके कारण भारत वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 36वें स्थान पर पहुँच गया है। 2024 की पहली तिमाही में चीन का रियल एस्टेट निवेश 2023 की पहली तिमाही की तुलना में 9.5 परसेंट घट कर 2.2 ट्रिलियन युआन, लगभग 0.31 ट्रिलियन डॉलर रह गया है। वहीं भारत में रीयल एस्टेट के क्षेत्र में विदेशी संस्थागत निवेश 2017 से 2022 के बीच तीन गुना बढ़कर 26.6 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया और अब मोदी 3.0 में 2025 तक रीयल एस्टेट क्षेत्र का जीडीपी में योगदान को 8 प्रतिशत से बढ़ा कर 13 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। यह foreign investors का भारत की सरकार और उसकी नीतियों में अटूट विश्वास का प्रतीक है। ये सारी परियोजनाएँ मेट्रो के साथ-साथ नॉन-मेट्रो सिटीज़ में भी बहुत तेजी से विस्तार कर रही हैं।

माननीया वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में सभी राज्यों से यह आग्रह भी किया है कि वे रीयल एस्टेट के ऊपर स्टांप ड्यूटी को कम करें। चूँकि यह स्टेट का सब्जेक्ट होता है, इसलिए उन्होंने सारे स्टेट्स से यह रिक्वेस्ट की है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए कहा है, क्योंकि इस पहल का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, जिससे कई शहरों में महिलाओं को मदद मिलेगी और वे अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

भारत के स्टॉक मार्केट की ग्रोथ की गति को देख कर आज विदेशी निवेशक भी हैरान हैं। आए दिन सेंसेक्स नए रिकॉर्ड छू रहा है। मैं सदन को अपना एक पर्सनल किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मैं कहीं पर गया हुआ था, तो एक जापानी व्यक्ति मुझसे आकर मिला। उसने पूछा कि क्या आप इंडिया से हैं, तब मैंने कहा कि जी हाँ, मैं इंडिया से हूँ। उसने कहा कि मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपकी सरकार को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने पूछा कि क्या हुआ? तब उसने कहा कि मैंने आपके यहाँ स्टॉक मार्केट में इंवेस्ट किया था, उसमें मुझे बहुत फायदा हुआ है, अब मेरा जीवन उस पैसे से बहुत आराम से कट रहा है। तो अगर जापान जैसे डेवेलप्ड कंट्री के लोग हमारे यहाँ आकर ऐसा इंवेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यह प्रधान मंत्री जी की जो नीतियाँ हैं और जिस तरीके से भारत का विश्व के अन्दर स्वरूप बना है, उसका फल है।

महोदय, जैसा कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि समस्या और अवसर के बीच एक मात्र अन्तर दृष्टिकोण का है। जिस प्रकार से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी तथा NHAI ने समस्याओं को अवसर में बदला है एवं भारत के राजमार्गों और एक्सप्रेसवेज़ के निर्माण को एक नयी ऊँचाई देकर सड़कों का जाल बिछा दिया है। इसके लिए मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारत में जिस गति से एक्सप्रेसवेज़ का निर्माण हो रहा है, वह किसी भी अन्य देश से कम नहीं है। सरकार की नीतियों से न केवल नागरिकों को अच्छी सड़कें मिल रही हैं, बल्कि

हजारों, लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं। Road Infrastructure Development के विकास पर हमारा फोकस अटूट है। 'भारतमाला' जैसी परियोजनाओं के कारण भारत के कोने-कोने में सड़कों का जाल विछाया जा रहा है। 2014 में हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क 91,287 किलोमीटर था, जो 2023 में बढ़कर 1,46,145 किलोमीटर हो गया है। जहाँ पहले यूपीए सरकार के दौरान प्रति दिन केवल 12 किलोमीटर सड़क बनती थी, वहीं आज मोदी सरकार में यह बढ़कर लगभग 30 किलोमीटर per day के हिसाब से बन रही है।

हमारी सरकार ने अभूतपूर्व सड़क संरचना का निर्माण किया है, जिसमें मुंबई में अत्याधुनिक 'अटल सेतु' से लेकर 'अटल टनल' है, जो world की longest highway tunnel है और यह 10,000 फीट ऊपर बनी है। वह भी एक मिसाल बन कर रह गई है। ये परियोजनाएँ न केवल यातायात को सुगम बनाती हैं, बल्कि आर्थिक विकास और सामाजिक एकीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

महोदय, जहाँ 2008 से 2012 के बीच पूरी दुनिया में विभिन्न सरकारें EV गाड़ियों के क्षेत्र में 800 मिलियन डॉलर खर्च कर 1 लाख से अधिक गाड़ियाँ बेच रही थीं, वहीं पर यूपीए सरकार में EV गाड़ियों पर कोई विशेष चर्चा नहीं हो रही थी। लेकिन आज श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में EV गाड़ियों की बिक्री में तेजी से वृद्धि हो रही है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, तो उत्तर प्रदेश हमारे देश का ऐसा पहला प्रदेश होगा, जहाँ EV और hybrid गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह से माफ है। आज भारत में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है, जहाँ EV वाहनों की संख्या 6,11,944 है। यह भारत के टोटल 28,30,565 इलेक्ट्रिक वाहनों में 18 परसेंट का महत्वपूर्ण योगदान देता है।

मोबाइल फोन के क्षेत्र में भी रिकॉर्ड उत्पादन भारत में हो रहा है तथा सबसे ज्यादा 89 देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ 2014 में हम 78 परसेंट इम्पोर्ट करते थे, वहीं आज हम 97 परसेंट self sufficient बन गए हैं।

महोदय, मैं बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती का उल्लेख करना चाहूँगा। वित्त वर्ष 2024 में हमारे बैंकिंग क्षेत्र का शुद्ध लाभ पहली बार तीन लाख करोड़ रुपए से ऊपर हो गया है। अभी बैंकों का एनपीए Insolvency Act के कारण कम हो रहा है और कर व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

काँग्रेस बेरोजगारी और गरीबी दूर करने का स्वांग रचती थी। यूपीए सरकार के 10 साल के शासन के दौरान जितनी नौकरियाँ पैदा हुईं, उससे कई करोड़ ज्यादा नौकरियाँ 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पैदा की हैं। आज एमएसएमई के पंजीकरण पोर्टल पर जो लोग हैं, उनकी संख्या कुल मिलाकर 20 करोड़ है। एनडीए सरकार में 10 साल की अवधि में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से भी बाहर निकाला गया है।

हमारा लक्ष्य है कि हम भारत के युवाओं को job-creators बनाएं। बजट में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास की योजनाओं की घोषणा की गई है। जिसमें पाँच वर्षों में दो लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव योजना, रोजगार मेला,

प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना, आदि नए अवसर देने के लिए नित्य अग्रसर हैं और हमारा फोकस नए रोजगार प्रदान करना है।

'पीएम स्वनिधि योजना' रेहड़ी-पटरी वाले भाई-बहनों के लिए एक संजीवनी बनी है और इसके अंतर्गत देश भर में 64 लाख से अधिक लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। इस बार मोदी जी ने जो गारंटी दी है, जो मोदी गारंटी कहलाती थी, वह रोजगार और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दी है। अगर कोई बेरोजगार है और वह कोई रोजगार करना चाहता है, तो मोदी सरकार 'मुद्रा योजना' के तहत उसे लोन उपलब्ध कराएगी। इसके तहत पहले 10 लाख रुपए तक का collateral free loan मिलता था, अब उसको बढ़ा कर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। जिससे उन युवाओं को काफी मदद मिलेगी, जो अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हैं। इससे यूपी जैसे राज्य में 24 लाख लाभार्थी होंगे। आज मुद्रा लोन के द्वारा 58 लाख लाभार्थी को 43 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त हमने एक महत्वाकांक्षी इंटर्नशिप कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत अगले पाँच वर्षों में 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को अवसर मिलेगा। यह पहल न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएंगी, बल्कि हमारे युवाओं को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल से लैस करेगी। इस योजना से कंपनी और युवाओं, दोनों को फायदा मिलेगा।

महोदय, इनकम टैक्स के क्षेत्र में भी प्रत्यक्ष करों को कम करके व विवाद में पड़े लंबित मामलों को हल करने के प्रावधान लाए गए हैं। इससे करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा तथा विवाद में फंसे पैसे भी निकल सकेंगे।

उत्तर प्रदेश की 'एक जनपद एक उत्पाद' (One District One Product - ODOP) योजना स्थानीय शिल्प और परंपरागत उद्योगों को नया जीवन दे रही है, जिसे कई राज्य और देश अपना रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य, चूँकि आपका समय समाप्त हो गया है, इसलिए अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए। वैसे भी नियमों में पढ़ कर बोलना अलाऊ नहीं है, इसलिए आप समाप्त कीजिए।

श्री संजय सेठ: महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के विकास और केंद्रीय बजट 2024-25 में हमारे राज्य के लिए किए गए प्रावधानों के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं पुनः प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने एक ऐसा बजट दिया है, जो विकसित उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर और आगे ले जाएगा। इस बजट में उत्तर प्रदेश को लगभग 3 लाख, 70 हजार करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। यह राशि केंद्रीय करों, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और विशेष सहायता से आएगी।...(**समय की घंटी**)... केंद्रीय करों से हमें 2.24 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे और यूपी के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। यूपी के 75 जिलों का डिजिटल सर्वे होगा और नेचुरल फार्मिंग का सबसे ज्यादा लाभ यूपी को होगा तथा पीपीपी मोड से 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कृपया आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री संजय सेठ : सर, अब मैं खत्म कर रहा हूँ।

योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। सुरक्षित उत्तर प्रदेश होने का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। पिछले साल की तुलना में इस साल हमारी अर्थव्यवस्था 8 परसेंट बढ़ी है। 2017 में हम देश की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, अब हम दूसरे नंबर पर आ गए हैं। उद्योगों के मामले में भी हमने बड़ी छलांग लगाई है।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य, अब आप समाप्त कीजिए।...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सेठः हमारे पास 15 औद्योगिक क्षेत्र, 12 विशेष पार्क और 4 विकास केंद्र हैं।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, अब आप बैठिए। डा. फौजिया खान।

श्री संजय सेठ : ठीक है। धन्यवाद, सर।

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak. I stand here to participate in the discussion on the Union Budget, 2024-25.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आपके पाँच मिनट्स हैं।

DR. FAUZIA KHAN: Yes, Sir. Every citizen of this country has a right over his share in the Budget because every rupee that the Government spends comes from the pocket of every citizen. A balanced distribution of funds is, therefore, the minimum expectation from any budget. And, therefore, budget should not become political tools, no matter what the political compulsions are. We all know that Maharashtra is the highest revenue giving State. So, Maharashtra, certainly, does not deserve to be neglected. This is a State where 66 per cent of the State has been declared drought affected. Drought had been officially declared in 1,532 out of 2,292 revenue circles in 2023. About 40 *tehsils* in 19 districts are facing acute drought conditions. In Marathwada alone, the region from where I come, 2,311 farmers have committed suicide in the last two years. सर, आंध्र प्रदेश के अमरावती में एक सपना साकार करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और मेरे महाराष्ट्र के अमरावती में, जहां पिछले 6 महीनों में

557 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, उस मराठवाड़ा-विदर्भ के पूरे विभाग को इरीगेशन के लिए, पानी के लिए केवल 600 करोड़ रुपये दिए जाते हैं, जो वहां मेरे किसान भाइयों के जीने-मरने का प्रश्न है! सर, जो प्यासा किसान भाई आकाश की ओर देखते-देखते अपनी जान दे देता है, क्या उसका इतना ही मोल है?

†سر، آندھراپردیش کے امراوتی میں ایک سپنا ساکار کرنے کے لیے 15,000 کروڑ روپے دیے جاتے ہیں اور میرے مہاراشٹر کے امراوتی میں، جہاں پچھلے چھ مہیوں میں 557 کسانوں نے خودکشی کی ہے، اس مراٹھواڑہ ودربھ کے پورے وبھاگ کو اِریگیشن کے لیے، پانی کے لیے صرف 600 کروڑ روپے دیے جاتے ہیں، جو وہاں میرے کسان بھائیوں کے جینے مرنے کا سوال ہے، سر جو پیاسا کسان بھائی آکاش کی طرف دیکھتے دیکھتے اپنی جان دے دیتا ہے، کیا اس کا اتنا ہی مول ہے؟

Sir, there is a project, a river diversion and linking scheme that aims to divert rain water that flows from Sahyadri mountains into the sea and gets wasted. This water needs to be diverted to the Godavari basin for irrigation to this drought prone area. The DPR has been prepared by the NWBA. The Government needs to grant some funds under the *Pradhan Mantri Krishi Sinchayi Yojana*. What the Union Government has to do is to give environmental clearance and forest clearance. सर, इस फंड से लाखों किसान भाइयों की निराशा दूर हो सकती है, लाखों परिवारों के जीवन में प्रकाश आ सकता है, लेकिन क्या ऐसे पोलिटिकल कम्पल्शंस के साथ ही हम इतना बड़ा देश चलाएंगे? इन परिस्थितियों में 600 करोड़ कितने कम होते हैं, इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी।

सर, 15 किलोमीटर का एक बाईपास रोड है, जो नेशनल हाईवे-61 का भाग है। इसका एस्टीमेट कॉस्ट जो सरकार द्वारा तैयार किया गया, वह 430 करोड़ था। जब बिड हुई तो एल-1 लगभग 30 प्रतिशत low था, यानी 110 करोड़ कम में बिड छूट गई। सर, यह कैसे हुआ? एस्टीमेट्स बनाते समय हमारे अधिकारी क्या कर रहे थे? यहां दो ही बातें हो सकती हैं कि या तो एस्टीमेट बनाने में भ्रष्टाचार या कम दर्जे का काम करने के लिए ग्रीन सिग्नल। एस्टीमेट्स कैसे बनते हैं, जब 110 करोड़ रुपये बच सकते हैं? हमारे ऑफिशिल्स की जो इतनी बड़ी यंत्रणा है, वह क्या करती है? सुना है, स्टेट की एक एस्टीमेट कमिटी होती है। यह कमिटी नॉन-फंक्शनल है या टूथलेस है? सर, क्या बड़े प्रोजेक्ट्स में एस्टीमेट्स एग्जामिन नहीं होने चाहिए? यह तो एक उदाहरण है, जो मैं दे रही हूं। ऐसे कितने रोड्स हैं, कितने ब्रिजेज़ हैं और कितना infrastructure होगा। सर, देश में एक विजिलेंस कमीशन है, जो अस्तित्व में है। This Commission deserves to have much, much sharper teeth than the ED and the CBI. अगर ऐसा होता, तो ब्रिज collapse होना, roads में crack होना, छतें गिरना, रेलवे एक्सीडेंट्स होना, water clog होना, ये सब दिखना बंद हो जाता। साथ ही हमें अपने बजट में इतने पैसे बच सकते थे कि अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के अन्याय रोक सकते थे,

† Transliteration in Urdu script.

†سر، اس فنڈ سے لاکھوں کسان بھائیوں کی نراشا دور ہوسکتی ہے،لاکھوں خاندانوں کے جیون میں پرکاش آسکت ہے، لیکن کیا ایسے پالیٹیکل کلمپلشنس کے ساتھ ہی ہم اتنا بڑا دیش چلائیں گے؟ ان پرستھتیوں میں 600 کروڑ کتنے کم ہوتے ہیں، اس کی ایک مثال میں دینا چاہتا ہونگی۔

سر، پندرہ کلومیٹر کا ایک بائی پاس روڈ ہے، جو نیشنل ہائی وے-61 کا حصہ ہے۔ اس کا اسٹیمیٹ کاسٹ تھا، lowاجو سرکار کے ذریعہ تیار کیا گیا، وہ 430 کروڑ تھا۔ جب بِڈ ہوئی تو ایل 1 لگ بھگ تیس فیصد یعنی 110 کروڑ کم میں بڈ چھوٹ گئی۔ سر، یہ کیسے ہوا؟ ایسٹیمیٹ بناتے وقت ہمارے ادھیکاری کیا کررہے تھے؟ یہاں دو ہی باتیں ہوسکتی ہیں کہ یا تو ایسٹمیٹ بنانے میں بھرشٹاچار یا کم درجے کا کام کرنے کے لیے گرین سگنل۔ ایسٹیمیٹ کیسے بنتے ہیں، جب 110 کروڑ روپے بچ سکتے ہیں ہمارے آفیشیلس کی جو اتنی بڑی ینترنا ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ سنا ہے، اسٹیٹ کی ایک ایسٹیمیٹ کمیٹی ہوتی ہے۔ یہ کمیٹی نان فنکشنل ہے یا ٹوتھ لیس ہے؟ سر، کیا بڑے پروجیکٹس میں ایسٹمیٹ ایگزامن نہیں ہونے یہ تو ایک مثال ہے، جو میں دے رہی ہوں۔ ایسے کتنے روڈس ہیں، کتنے برج ہیں اور کتنا چاہیے؟ ہوگا۔ سر، دیش میں ایک وجیلینس کمیشن ہے، جو استتو میں ہےinfrastructure۔ This Commission deserves to have much, much sharper teeth than the ED and the CBI اگر ایسا ہوتا ہے، تو برج کالیپس ہونا روڈ میں کریک ہونا، چھتیں گرنا، ریلوے ایکسیڈینٹ ہونا، واٹر ہونا، یہ سب دکھنا بند ہوجاتا۔ ساتھ ہی ہمیں اپنے بجٹ میں اتنے پیسے بچ سکتے تھے کہ دوسرے .کلاگ because prevention of corruption is راجیوں میں بھی اس طرح کی ناانصافی روک سکتے تھے۔ much more important than imprisoning people after the damage is done. ...*(Time-bell rings)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आपका बोलने का समय पूरा हो गया है।

DR. FAUZIA KHAN: Sir, can I take one more minute?

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आप अपनी बात समाप्त करें।

डा. फौज़िया खान: अगर 15 किलोमीटर रोड से 110 करोड़ रुपये बच रहे हैं, तो 47, 400 से कितने बचेंगे? अगर पैसे बचे तो किसान भाइयों को प्यासा क्यों रहना पड़ेगा?

†اگر پندرہ کلومیٹر روڈ سے 443 کروڑ روپے بچ رہے ہیں، تو 7:/733 سے کتنے بچیں گے؟ اگر پیسے بچے تو کسان بھائیوں کو پیاسا کیوں رہنا پڑے گا؟

† Transliteration in Urdu script.

Allocation doesn't necessarily imply that funds are effectively benefitting the end-user. If we focus on the principle of 'penny saved is penny gained', we can start looking at the Budget through a different perspective.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): प्लीज़, अपनी बात समाप्त करें।

DR. FAUZIA KHAN: Obviously, Sir, leakages must be stopped. Legitimized corruption must stop, and, if all these guidelines are followed ... ...(*Time-bell rings*)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य, आपका बोलने का समय समाप्त हो गया है।

DR. FAUZIA KHAN: Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): धन्यवाद। श्री अरुण सिंह, आपके पास बोलने के लिए 20 मिनट का समय है।

श्री अरुण सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने जो केंद्रीय बजट 2024-25 सदन में पेश किया है, उसकी चारो ओर प्रशंसा हो रही है। चाहे आम जन हो, चाहे छोटे-बड़े व्यापारी हों और चाहे अर्थशास्त्री हों, अगर आप देखेंगे, तो पाएंगे कि न्यूज़पेपर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और पत्र-पत्रिकाओं में भी इस बजट की चारो ओर प्रशंसा ही प्रशंसा हो रही है। इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं।

सर, अगर इस बजट को देखें तो यह बजट रोज़गारपरख भी है। किस प्रकार से employment create किया जाए, उनकी स्किलिंग की जाए और उनको अलग-अलग रोज़गार और स्वरोज़गार के अवसर प्रदान किये गये हैं। यह बजट हमारे गरीब कल्याण के प्रति समर्पित भी है, किसान के उत्थान के लिए इसमें बहुत सारी बातें हैं और इस बजट में महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता भी दिखती है। देश में जो सबसे बड़ा रोज़गार देने वाला एमएसएमई सेक्टर है, उस एमएसएमई सेक्टर को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाए, वे कैसे अधिक से अधिक रोज़गार दे सकें, इसके लिए भी इस बजट में अनेकों उपाय किए गए हैं। इस बजट में सरलीकरण भी है। अगर हम इसको कुल मिलाकर nutshell में देखें तो अमृतकाल में विकसित भारत के संकल्प को प्राप्त करने की दिशा में यह बजट माननीय निर्मला सीतारमण जी ने सदन में रखा है।

मान्यवर, यह बजट ऐतिहासिक है, इसको मैं ऐतिहासिक इसलिए कहूंगा कि देश में 60 साल बाद पहली बार किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव हुआ और वह जीत कर आया तो माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीत कर आया है। यह बजट इसलिए भी ऐतिहासिक है कि देश में वित्त मंत्री जी ने जब बजट रखा, तो सामान्य रूप से दो बार, तीन बार लोग Budget रखते हैं, लेकिन मोरारजी देसाई जी के बाद पहला ऐसा मौका है, जब माननीय वित्त जी ने 7वीं बार बजट को जनता के समक्ष रखा है। यह इस बात को दर्शाता है कि लोगों को किस प्रकार का अटूट विश्वास माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी की नीतियों पर, उनके कार्यों में और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की उपलब्धियों में है।

मान्यवर, हम अगर बजट का साइज़ देखे, क्योंकि बजट में total expenditure 48 लाख, 21 हज़ार करोड़ रुपये का है। सर, यूपीए का जब समय था, अगर हम वर्ष 2013-14 का बजट देखें तो वह 16 लाख, 65 हज़ार करोड़ रुपये का था। इसका मतलब यह हुआ कि माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह जो बजट रखा गया है... इसमें जो खर्चें होंगे, यूपीए के समय से विकास के लिए तीन गुना अधिक खर्चें हो रहे हैं। इसी के साथ-साथ अगर आमदनी भी देखें, तो यह सबको मालूम था कि जब यूपीए की सरकार थी, किस प्रकार से लीकेज था, किस प्रकार से भ्रष्टाचार था, चारों ओर अंधकारमय ही था। अगर हमारे बजट को देखें, तो इसमें 32 लाख 7 हजार करोड़ का पूरा रेवेन्यू receipt है और यूपीए के समय में यह 32 लाख की जगह केवल 10 लाख 55 हजार था। अब 10 लाख 55 हजार में क्या खर्च करेंगे, क्या लोगों को राहत दे पाएंगे, यह सोचने का विषय है। उसमें आर्थिक विकास किस प्रकार से चल रहा था, वह लोगों को मालूम ही है।

मान्यवर, यूपीए के समय में लालफीताशाही थी, policy paralysis था, घोटाला पे घोटाला था, मंत्री, अधिकारी जेल में जा रहे थे और top five fragile countries में भारत का नाम था। Top five fragile का मतलब low growth है। ग्रोथ सबसे कम थी। दूसरा, inflation सबसे अधिक था, high external debt और poor financial health था, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, इनकी हालत बिल्कुल जर्जर हो गई थी। यह यूपीए का समय था। लोग इस पर चिंता व्यक्त कर रहे थे और पत्र-पत्रिकाओं में भी लगातार इस बात का उल्लेख हो रहा था, लेकिन यह प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था का परिणाम है कि आज इतने बड़े बजट को हम सदन के सामने देख रहे हैं, जिससे जनता का कल्याण होगा। इसी का नतीजा है कि हमारे बजट का साइज बढ़ रहा है। यूपीए के समय में हम 11वीं अर्थव्यवस्था थे। लोगों को यह लग रहा था कि 11वीं अर्थव्यवस्था ही हम होंगे, क्योंकि उस समय के जो न्यूज पेपर थे, वे जो क्वोट करते थे, वे यही क्वोट करते थे कि फिर एक बार करप्शन, फिर एक बार policy paralysis, लेकिन बजट का साइज लगातार बढ़ रहा है, इसके कारण जो 11वीं अर्थव्यवस्था थी, उससे हम 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंच चुके हैं और यह हम नहीं, पूरा देश ही नहीं, बल्कि विश्व के सभी संगठन, IMF and World Bank सभी एक सुर में कह रहे हैं कि 2027 में मोदी जी के नेतृत्व में हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, ये सभी एक सुर से कह रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का ढेर सारा अभिनंदन और वंदन करता हूं।

मैं financial indicators आपके समक्ष रखता हूं। हमारी जो सरकार माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है, वित्त मंत्री जी ने लगातार किस प्रकार से वित्तीय अनुशासन का पालन किया जाए, हमारे fiscal discipline है, उसको कायम करते हुए खर्चा भी किया जाए, जो आम जनमानस हैं, उनकी मदद भी की जाए, विकास भी किया जाए, infrastructure क्रिएट किया जाए और उसको ध्यान में रखते हुए इसके लिए financial discipline को पूरे तरीके से उन्होंने manage किया है। मान्यवर, हमारा capital expenditure 11 हजार करोड़ का, यह कोई छोटी सामान्य बात नहीं है। यूपीए के समय में ढाई लाख करोड़ भी नहीं होता था। अगर 11 हजार करोड़ रुपये कैपिटल एक्स्पेंडीचर हो रहे हैं, उसी का नतीजा है कि चारों ओर सड़कों का जाल फैल रहा है। कहीं भी यहां से चले जाइए, चाहे मेरठ चले जाइए, 40 मिनट का समय लगेगा, जयपुर ढाई घंटे में चले जाइए। देश के कोने में कहीं दूसरे स्थान पर जाइए, जहां चार घंटे-पांच घंटे लगते थे, अब तुरंत आप वहां पहुंच जाएंगे। वह समय की दूरी कितनी कम हो गई है कि लोगों को जाने में सुविधा मिलती है और इसी का नतीजा है कि आज हमारे एयरपोर्ट डबल हो गए हैं। इसी का नतीजा है, हमारे रेल मंत्री जी बैठे हैं, किस प्रकार से वंदे भारत ट्रेन चल रही है। अलग-अलग हाई स्पीड ट्रेन चल रही है, रेलवे के जो हमारे ट्रैक्स हैं, उनमें तीन गुना रफ्तार से काम हो रहा है। अनेकों infrastructure create हो रहे हैं, वह उसकी देन यही है कि मोदी जी की प्राथमिकता है कि infrastructure पर, capital expenditure पर खूब पैसा खर्च करो और जब capital expenditure पर पैसा खर्च करते हैं, infrastructure create करते हैं, तो फिर पैसे का circulation भी एक बार नहीं, तीन बार होता है, इसी के कारण हमारी इकोनॉमी भी बढ़ रही है। मान्यवर, यह जो वित्तीय अनुशासन है, इसमें अनेकों चीजों को ध्यान में रखा है, उसमें कोई कंजूसी नहीं की है। फिर भी इसको मेन्टेन किया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया और उसमें भी कोई compromise नहीं किया। वह पांच साल तक लगातार मिलता रहेगा। किसानों को 60 हजार करोड़ रुपये का बजट में आवंटन है। यही यूपीए की सरकार थी, हमें मालूम है कि एक बार इन्होंने 60 हजार करोड़ रुपये का लोन वेवर किया। उस लोन वेवर के बाद, कुछ का हुआ, कुछ का नहीं हुआ, लगातार उसका दस साल तक ढिंढोरा पीटते रहे।

[**उपसभाध्यक्ष (सुश्री कविता पाटीदार)** *पीठासीन हुईं।*]

यह प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार है, जो 60 हजार केवल एक साल के लिए नहीं, बल्कि 60 हजार हर साल किसानों को उनके अकाउंट में डायरेक्ट भेजने का काम कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस का समय था, जब लोगों के पक्के घर-मकान नहीं बनते थे, लेकिन सबके पक्के घर-मकान होने चाहिए। उस समय हमें मालूम है कि जो मकान इंदिरा आवास योजना में बनते थे, तो उसका आधा पैसा रिश्वत में चला जाता था। आप अगर गांव में जाकर देखेंगे इंदिरा आवास योजना में, उसमें भूसा दिखेगा, वे मकान रहने लायक नहीं हैं, क्योंकि पैसा करप्शन की भेंट चढ़ जाता था। आज चार करोड़ मकान बन गए, तीन करोड़ और मकान बनाने की घोषणा हुई है। उसके साथ-साथ एक करोड़ मकान अर्बन एरिया में बनाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया

है। युवाओं को रोजगार मिले, स्व-रोजगार मिले, उनको अनेकों काम करने की सुविधा मिले, इसके लिए जो 'Education, Employment and Skilling' है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन कोई कल्पना कर सकता था कि 10- 20 हजार करोड़ नहीं, बल्कि 1 लाख, 48 हजार करोड़ रुपये का युवाओं के लिए प्रावधान किया गया है! युवा अपने स्किल को बढ़ाएं, नौकरी करें, apprentice करें और उसके बाद जाकर वे अपना उद्योग खोल सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और कहीं जाकर नौकरी भी कर सकते हैं। यह ऐतिहासिक कदम है। देश भर का युवा इसके लिए अभिनंदन कर रहा है, माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी का वंदन कर रहा है ।

महोदया, महिला सशक्तीकरण के लिए प्रधान मंत्री मोदी जी और उनकी सरकार सदैव प्रतिबद्धित है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तीन लाख करोड़ रुपये महिला सशक्तीकरण के लिए प्रावधान है।

जब तक गांव में विकास नहीं होगा, तो हम देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। देश की अधिकांश आबादी गांव में रहती है। देश की मूल आत्मा गांव में ही बसती है, इसलिए ग्रामीण विकास के लिए 2 लाख, 66 हजार करोड़ रुपये का इसमें प्रावधान है। सबको पीने का पानी मिले, इसके लिए भी 70 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि fiscal discipline, अपने वित्तीय अनुशासन को भी मेन्टेन किया और उसके साथ-साथ खर्चों में भी कटौती नहीं की। यह गरीब और किसान के प्रति समर्पित सरकार है, यह इसमें दिखता है। हमारा जो fiscal deficit है, वह कुल मिलाकर 4.9 परसेंट है। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी, इतना अधिक खर्च करने के बाद भी यह 4.9 परसेंट है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार मोदी जी के मूल मंत्र, 'Reform, perform and transform' से चल रही है। अगले वर्ष हम 4.5 परसेंट, जो fiscal deficit है, उसको अचीव करने में जरूर सफल होंगे।

दूसरा, जो Current Account Deficit है, वह financial indicator है। इसका मतलब होता है कि हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना इम्पोर्ट कर रहे हैं। कितना पैसा हमारा बाहर जा रहा है, विदेशों में जा रहा है और कितना पैसा विदेश से हमारे देश में आ रहा है। यह देश की समृद्धि और देश के उद्योग की, जो competency है, उसको दर्शाता है। यूपीए के समय में क्या होता था, यह हम सबको मालूम है और 2012-13 में क्या स्थिति थी। हमारे जयराम रमेश जी बैठे हैं, यूपीए के समय में जो Current Account Deficit था, वह minus 4.8 था, जो कि alarming था और स्थिति यह आ गई थी कि आने वाले समय में न इम्पोर्ट कर पाएंगे, न तेल आएगा, यह स्थिति यूपीए के समय में थी। आज हमारे समय में, अगर इसको देखेंगे, तो जो Current Account Deficit है, वह एक परसेंट से भी कम है। ऐसा इसलिए हुआ कि पहले इनके समय में दो मोबाइल कम्पनियां थीं और अब 200 से अधिक मोबाइल कम्पनियां हैं। यही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले हम 50 हजार करोड़ रुपये का मोबाइल इम्पोर्ट करते थे। जब इम्पोर्ट करेंगे, तो हमारा Current Account Deficit बढ़ेगा और अब केवल 7 हजार करोड़ रुपये का इम्पोर्ट करते हैं। इसका मतलब है कि मोबाइल कम्पनियां अधिक से अधिक भारत में लग रही हैं। पहले इनके समय में एक्सपोर्ट तो न के बराबर था, केवल 1,500 करोड़ रुपये का मोबाइल का एक्सपोर्ट होता था। यूपीए के समय में यह नगण्य था। महोदय, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पीएलआई लेकर

आए, लोगों को प्रोत्साहित किया, उससे हमारा एक्सपोर्ट, हमारे मोबाइल का एक्सपोर्ट विदेशों में 1 लाख, 28 हजार करोड़ रुपये का हो रहा है। यह हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

महोदय, आज electronic export में नए-नए उद्योग लग रहे हैं। उन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है। यह आंकड़ा 29 billion dollars है, जो पिछले साल से 23 परसेंट बढ़ा है। मतलब हमारा जो electronic export है, वह लगातार ग्रोथ की दिशा में है और वह भी डबल डिजिट से ऊपर की दिशा में है।

महोदय, हम डिफेंस के लिए यह जरूर कहना चाहेंगे कि छोटे-छोटे पाट्र्स भी विदेशों से मंगाए जाते थे। आजादी के इतने साल बाद तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन क्या वे पाट्र्स यहाँ नहीं बन सकते थे, क्या हमारे यहाँ competency नहीं थी? महोदय, इनकी यह करने की इच्छा ही नहीं थी, बल्कि इसके पीछे इच्छा कुछ और थी। महोदय, हमने बहुत सारे घोटाले, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, बोफोर्स घोटाला आदि जैसे घोटाले सुने थे और इसके पीछे घोटाला यह भी था कि डिफेंस का जितना सामान इम्पोर्ट करोगे, उतना ही कहीं न कहीं kickbacks में जाएगा। हमारे समय में, मोदी जी के नेतृत्व में डिफेंस का एक्सपोर्ट 20 हज़ार, 915 करोड़ है, जो कि इनके समय से 18 गुना अधिक है। हम लोग डिफेंस में इतने गुना अधिक एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यह एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। आज के दिन हमारे डिफेंस का जो उत्पादन है, वह 1 लाख, 26 हज़ार करोड़ रुपये है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह इसीलिए हुआ है, क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री जी Make-in-India, Vocal-for-Local के संकल्प को सिद्धि से प्राप्त करने के लिए अनेक योजनाएं लेकर आए।

महोदय, जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात है, हम सभी को मालूम है कि जब यूपीए का समय था, तब क्या इन्फ्लेशन था? महोदय, यह इन्फ्लेशन 2009 में 11 परसेंट, 2010 में 11.99 परसेंट, 2011 में 9 परसेंट, 2012 में 9.48 परसेंट, 2013 में 10.02 परसेंट था। यानी डबल डिजिट का इन्फ्लेशन था, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ज्ञान देने का काम कर रही है! यह डबल डिजिट का इन्फ्लेशन एक साल नहीं, बल्कि लगातार पाँच सालों तक रहा था, लेकिन यह मोदी जी की सरकार है, जिसने इन्फ्लेशन को 4 परसेंट के आसपास रखने का काम किया है, इसलिए हम प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, पर क्या ये हमें सिखाएंगे!

महोदय, हम FDI के बारे में जरूर कहना चाहेंगे। महोदय, चाहे IMF हो, World Bank हो, आज अनेक पत्र-पत्रिकाएँ भारत को Star Performer बोल रही हैं, Bright Spot बोल रही हैं, आज भारत की अलग-अलग संज्ञा से तारीफ कर रही हैं। IMF ने कहा है कि Global Growth में भारत का 16 परसेंट योगदान होगा। यानी आने वाले समय में भारत का ग्लोबल ग्रोथ में जो कंट्रीब्यूशन है, वह इस प्रकार से होगा कि भारत विश्व के लिए संकटमोचक साबित होगा - यह IMF ने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं।

महोदय, कांग्रेस के लोग 28 अगस्त, 2013 को भूल गए हैं। इनके समय में रुपये की क्या फ्लक्चुएशन होती थी। महोदय, 28 अगस्त, 2013 को, जब US Federal Reserve ने कोई घोषणा की थी, उसके बाद एक दिन में रुपया 29 परसेंट गिर गया था, जो कि 18 सालों में सबसे अधिक कमजोर रुपया साबित हुआ था। यह इनके समय की करतूत थी। बाहर से पैसा आता था और ECB

के माध्यम से आता था। महोदय, Promissory Notes में कितना बड़ा घोटाला हुआ था, उसके बारे में सभी को मालूम है।

महोदय, इनके समय में, दस सालों में केवल 298 बिलियन डॉलर की एफडीआई आया था, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में इस 298 बिलियन डॉलर की जगह 667 बिलियन डॉलर का आया है, जो दोगुना से अधिक है। इसी प्रकार से इनके समय में Forex Reserves 304 था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 668 बिलियन डॉलर है और आज भारत सिंगापुर, जर्मनी, रशिया, यू.के., स्पेन, ब्राज़ील से ऊपर आकर चौथे नंबर पर Forex Reserves के रूप में जाना जाता है।

महोदय, बैंकिंग - जो phone-banking थी, उसके बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि किस प्रकार से एनपीए बढ़ रहा था। यह 7 परसेंट, 8 परसेंट, 10 परसेंट था, लेकिन मोदी जी 2016 में IBC लेकर आए, IBC के बाद transparent policy भी लाए और उसी का नतीजा है कि 1000 से अधिक कंपनियों का 3 लाख, 30 हजार करोड़ रुपये का लोन रिज़ॉल्व भी हुआ। इसी के साथ, 28,000 केसेज़ ऐसे हैं, जिनमें आईबीसी के डर से वे दस लाख करोड़ के एसेट एडमिशन से पहले ही रिज़ॉल्व हो गए, इसका मतलब जो वे बैड डेट्स थे, एनपीए थे, वे किस प्रकार से एसेट में कंवर्ट कर रहे हैं, यह देखने की बात है। उनके समय लॉस था, आज केवल बैंक का पीएसयू ही ले लें, तो 1,40,000 करोड़ रुपये का प्रॉफिट है। और तो और, पीएसयू बैंक डिविडेंड देने लगे हैं। 19 जुलाई को देखें, तो चार बैंकों ने सरकार को 6,481 करोड़ रुपये डिविडेंड देने का काम किया है। एसबीआई ने 21 जून, 2024 को 6,959 करोड़ रुपये देने का काम किया है। जो पहले लॉस में थे, उन्हें कैपिटल देना पड़ता था, अब वे सरकार को डिविडेंड दे रहे हैं। यह कितना बड़ा चेंज है। यह इसलिए हो रहा है, क्योंकि प्रधान मंत्री, मोदी जी कहते हैं कि अगर नीति स्पष्ट हो, नीयत साफ हो, इरादे नेक हों, तो आप इच्छित परिणाम ला सकते हैं और यही इच्छित परिणाम... आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली जीडीपी भारत की है। एक साल नहीं, तीन सालों में सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। जहाँ मेक्सिको की जीडीपी 2.2 परसेंट, साउथ अफ्रीका की 0.9 परसेंट, चाइना की पाँच परसेंट, रूस की 3.2 परसेंट, वहीं इंडिया की जीडीपी ग्रोथ सात परसेंट से ऊपर है और तीन क्वार्टर में आठ परसेंट से ऊपर है। मध्यम वर्ग के लिए जरूर कहना चाहूँगा कि मध्यम वर्ग के लिए टैक्स का स्लैब बढ़ाया गया और उस टैक्स स्लैब को इनके समय से कंपेयर करेंगे, तो आठ लाख की इनकम को 78,000 रुपये का लाभ हो रहा है। जिनकी इनकम 12 लाख है, उन्हें इनकम टैक्स के माध्यम से इस वर्ष 13,400 रुपये लाभ हो रहा है। मैं यही कहूँगा कि इनकम टैक्स की रिटर्न्स में कई गुना जंप हुई है। कांग्रेस के द्वारा कहा जाता है कि मध्यम वर्ग मर गया, तो कहाँ से मर गया? 3,80,00,000 रिटर्न्स आपके समय फाइल होते थे, आज मोदी जी का नेतृत्व है, उनकी नीतियाँ हैं, पिछले साल 8,18,00,000 रिटर्न्स फाइल हुए हैं।

उपसभाध्यक्ष (सुश्री कविता पाटीदार): माननीय सदस्य, प्लीज़ कन्क्लूड कीजिए।

श्री अरुण सिंह: मैं थोड़ा ही बोलना चाहता हूँ। आज 15,10,00,000 डीमैट अकाउंट्स खुल गए हैं। यह मैं एक कविता के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहूँगा। प्रधान मंत्री, मोदी जी ने काशी में जो कविता कही थी, केवल उस कविता को कहकर समाप्त करूँगा।

" वह जो सामने मुश्किलों का अंबार है
उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है
चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा
इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है।
विकास के यज्ञ में परिश्रम की महक है
यही तो माँ भारती का अनुपम श्रृंगार है
गरीब-अमीर बने नए हिंद की भुजाएं
बदलते भारत की यही तो पुकार है।
देश पहले भी चला और आगे भी बढ़ा,
अब न्यू इंडिया दौड़ने को बेताब है
दौड़ा ही न्यू इंडिया का सरोकार है"

बहुत-बहुत धन्यवाद।"

THE VICE-CHAIRPERSON (MS. KAVITA PATIDAR): Thank you, hon. Member.

SPECIAL MENTIONS

THE VICE-CHAIRPERSON (MS. KAVITA PATIDAR): Now, Special Mentions. Shri Iranna Kadadi; not present. Dr. Fauzia Khan.

Concern over challenges faced by Children of Women Prisoners

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Madam, as on December 31, 2022, 1,537 women prisoners were living with 1,764 children in prisons. Children aged 0-6 years are permitted to live with their mothers in prison, an environment inappropriate for their development due to small spaces, lack of education, healthy meals and immunisation, which negatively impacts their mental and physical growth. The NCPCR Report reported that 62.5 per cent of prisons had creches within the jail, contrary to Supreme Court guidelines mandating these facilities outside. Children above six years are either cared for by relatives or placed in Government or voluntary institutions, often encountering financial difficulties, poor nutrition and vulnerability to illnesses. Irregular visits to imprisoned mothers also harm parent-child relationships.